कॉरपोरेट मिरर

मूल्यः ₹50

वर्षः 05 | अंकः04 | रायपुर, जुलाई 2026 | RNI. NO. CHHHIN/2022/86398

आर्थिक जगत का आईना

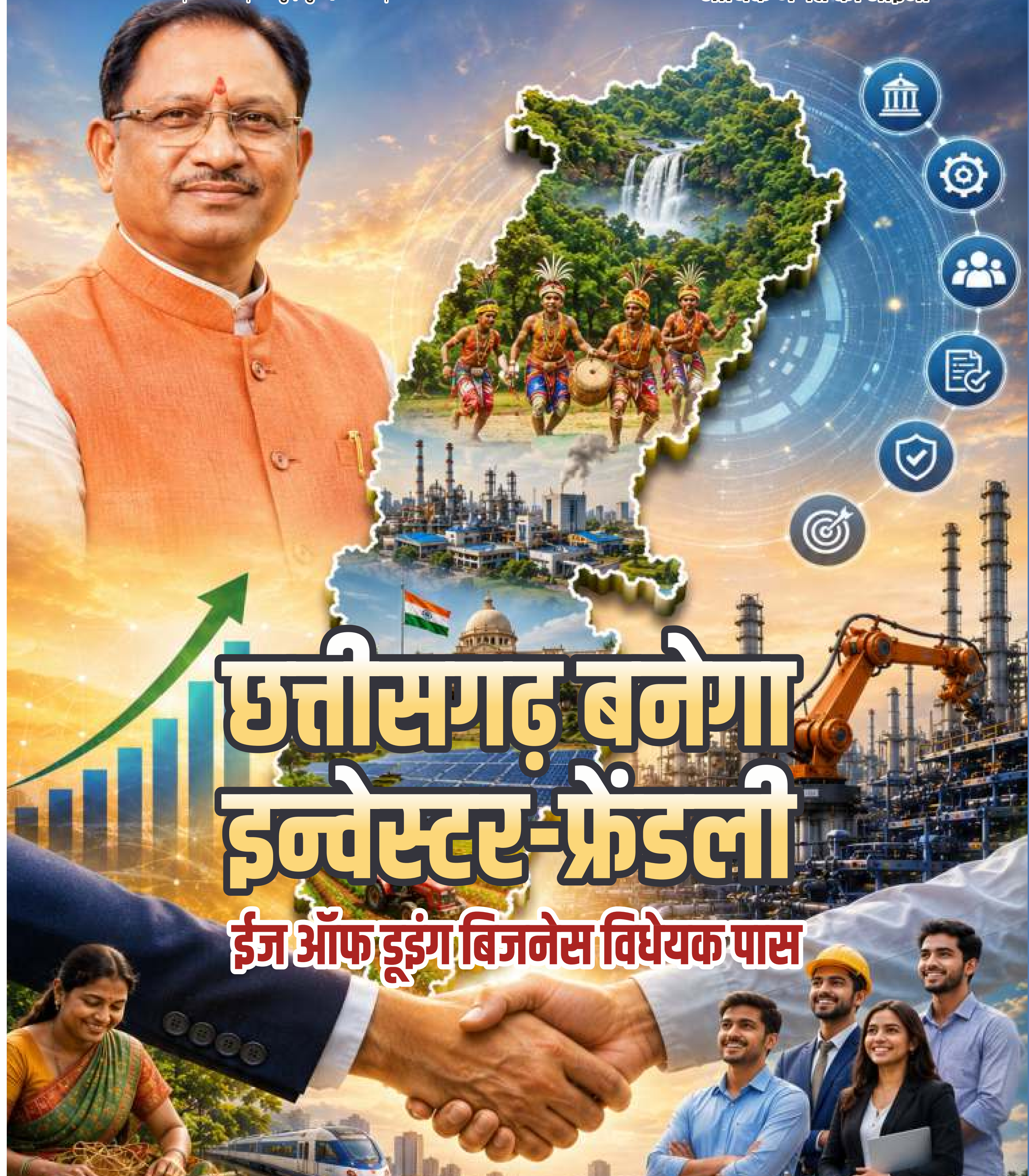

छत्तीसगढ़ बनेगा इन्वेस्टर-फ्रेंडली

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक पास

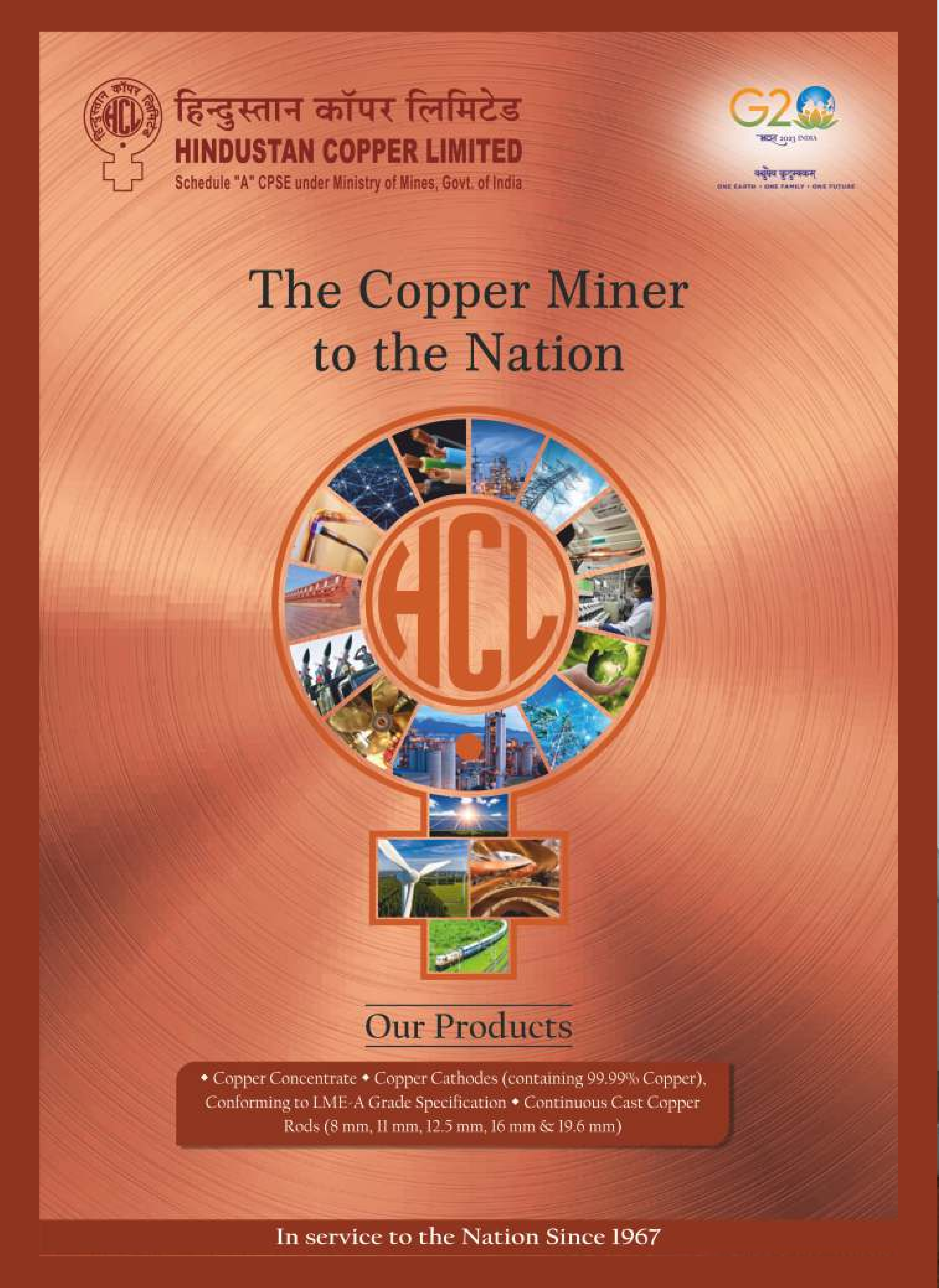

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
HINDUSTAN COPPER LIMITED
Schedule "A" CPSE under Ministry of Mines, Govt. of India
G20
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE
The Copper Miner to the Nation
HCL
Our Products
• Copper Concentrate • Copper Cathodes (containing 99.99% Copper), Conforming to LME-A Grade Specification • Continuous Cast Copper Rods (8 mm, 11 mm, 12.5 mm, 16 mm & 19.6 mm)
In service to the Nation Since 1967

Green AGROTECH
Polyhouse Structure
Rose Plant
Rose Flower Wholesaler
Drip System
Khamhardih Main Road, Opp. Banyan Tree, Khamhardih, Raipur 492007
Green.ravi11@gmail.com
7389991133, 8435741253, 9630010222

कॉरपोरेट मिरर

RNI. NO. CHHHIN/2022/86398

वर्षः 05 | अंकः 04 | रायपुर, जुलाई 2026

पृष्ठः 32 | मूल्यः ₹50

संपादक - सुमित यादव | **प्रबंध संपादक -** कैलाश यादव

सलाहकार संपादक
अर्चना दुबे

उत्तरप्रदेश ब्यूरो
आनंद मिश्रा

धमतरी ब्यूरो
चंदन शर्मा

झारखंड ब्यूरो
वीरेन्द्र श्रीवास्तव

दंतेवाड़ा ब्यूरो
आर. के. बैरागी

प्रसार प्रबंधक
ए.के.साहू

मध्यप्रदेश ब्यूरो
दिलीप शर्मा

डिजाइनिंग
स्काई ग्राफिक्स

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक **सुमित यादव** द्वारा रामा ऑफसेट प्रिंटर्स, शिवम मशीनरी टूल्स के पीछे, रिंग रोड नं. 2, सोनडोंगरी, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) से मुद्रित कर वर्मा निवास, नया मंगल बाजार, गुढ़ियारी, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) 492001 से प्रकाशित।

संपादक- कैलाश यादव* | **संपर्क- 7987832355**

www.corporatemirror.in

editor.corporatemirror@gmail.com

सिटी आफिस

57, द्वितीय तल, समवेत शिखर काम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान रायपुर (छत्तीसगढ़)

कैलाश यादव
संपादक

संपादक की कलम से

छत्तीसगढ़ में व्यापार सुगमता का नया सवेरा

छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार सुगमता) विधेयक को पारित करना राज्य के आर्थिक परिदृश्य में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह कदम न केवल राज्य में नए निवेश के द्वार खोलेगा, बल्कि स्थानीय उद्यमियों और कारोबारियों के लिए 'लालफीताशाही' (रेड टेपिज्म) के बोझ को भी कम करेगा। खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद, छत्तीसगढ़ को लंबे समय से एक ऐसे नीतिगत ढांचे की आवश्यकता थी जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बना सके। यह विधेयक उसी कमी को पूरा करने की एक गंभीर कोशिश दिखाई देता है।

इस विधेयक का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब उद्योग शुरू करने या उसे चलाने के लिए आवश्यक सरकारी मंजूरियों, लाइसेंस और एनओसी (NOC) की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा। अक्सर जटिल कागजी कार्रवाई और विभिन्न विभागों के चक्कर काटने के डर से नए उद्यमी कदम पीछे खींच लेते हैं। प्रक्रियाओं के डिजिटल होने और समय-सीमा तय होने से न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की राष्ट्रीय रैंकिंग में भी छत्तीसगढ़ अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकेगा।

किसी भी राज्य की प्रगति केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भर नहीं हो सकती; इसके लिए निजी निवेश और उद्यमशीलता का फलना-फूलना अनिवार्य है। जब राज्य में व्यापार करना आसान होगा, तो देश-विदेश के बड़े निवेशक छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। स्टील, सीमेंट और पावर जैसे पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ आईटी, फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे नए क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस विधेयक के जरिए एक प्रगतिशील विज़न पेश किया है। यदि इसे सही भावना और कड़े प्रशासनिक नियंत्रण के साथ लागू किया गया, तो यह विधेयक छत्तीसगढ़ को 'संसाधन-समृद्ध राज्य' से आगे बढ़ाकर देश के सबसे पसंदीदा 'इन्वेस्टमेंट हब' के रूप में स्थापित कर सकता है। व्यापार सुगमता का यह रास्ता, छत्तीसगढ़ की समग्र प्रगति का रास्ता है।

छत्तीसगढ़ बनेगा इन्वेस्टर फ्रेंडली

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक पास

रायपुर। छत्तीसगढ़ ने कारोबार और निवेश के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य विधानसभा ने छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट-2026 (EoDB Act) को मंजूरी दे दी है. इस कानून के लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां उद्योगों और कारोबारों को उनके जोखिम (रिस्क) के आधार पर वर्गीकृत कर अनुमति देने की व्यवस्था होगी. इसका सबसे बड़ा फायदा छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) को मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

देश का पहला रिस्क-बेस्ड बिजनेस मॉडल

नए कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिजनेस को उनके आकार, निवेश और गतिविधियों के आधार पर अलग-अलग रिस्क कैटेगरी में रखा जाएगा. कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए नियम आसान होंगे, जबकि बड़े और अधिक जोखिम वाले उद्योगों के लिए आवश्यक निगरानी जारी रहेगी. इस व्यवस्था से छोटे उद्यमों को उन्हीं नियमों और प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा, जो बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स पर लागू होती हैं.

छोटे कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत

Ease of Doing Business Act, 2026 के तहत छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारों के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी सरल बनाई है. ऐसे उद्यमों को कम दस्तावेज और कम औपचारिकताओं के साथ स्वीकृति मिल सकेगी. सरकार का मानना है कि इससे नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने में आने वाली बाधाएं कम होंगी और स्टार्टअप तथा MSME सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी.

सेल्फ-सर्टिफिकेशन से होगा काम

अब कम जोखिम वाले कई व्यवसायों में बार-बार होने वाले सरकारी निरीक्षण की जगह सेल्फ-सर्टिफिकेशन और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था लागू होगी. यानी उद्यमी स्वयं घोषित कर सकेगा कि वह निर्धारित मानकों का पालन कर रहा है. जरूरत पड़ने पर लाइसेंसधारी इंजीनियर, आर्किटेक्ट या अन्य अधिकृत विशेषज्ञों से प्रमाणन भी लिया जा सकेगा. इससे अनुमोदन प्रक्रिया तेज होगी और सरकारी हस्तक्षेप कम होगा.

सालाना रिन्यूअल की झंझट होगी खत्म

नए कानून के तहत कई अनुमतियों के लिए हर साल होने वाले रिन्यूअल की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी. इसकी जगह रिस्क-बेस्ड अनुपालन प्रणाली लागू होगी. इस बदलाव से कारोबारियों का समय बचेगा और उन्हें बार-बार एक ही दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बजाय अपने व्यवसाय पर अधिक ध्यान दे सकेंगे.

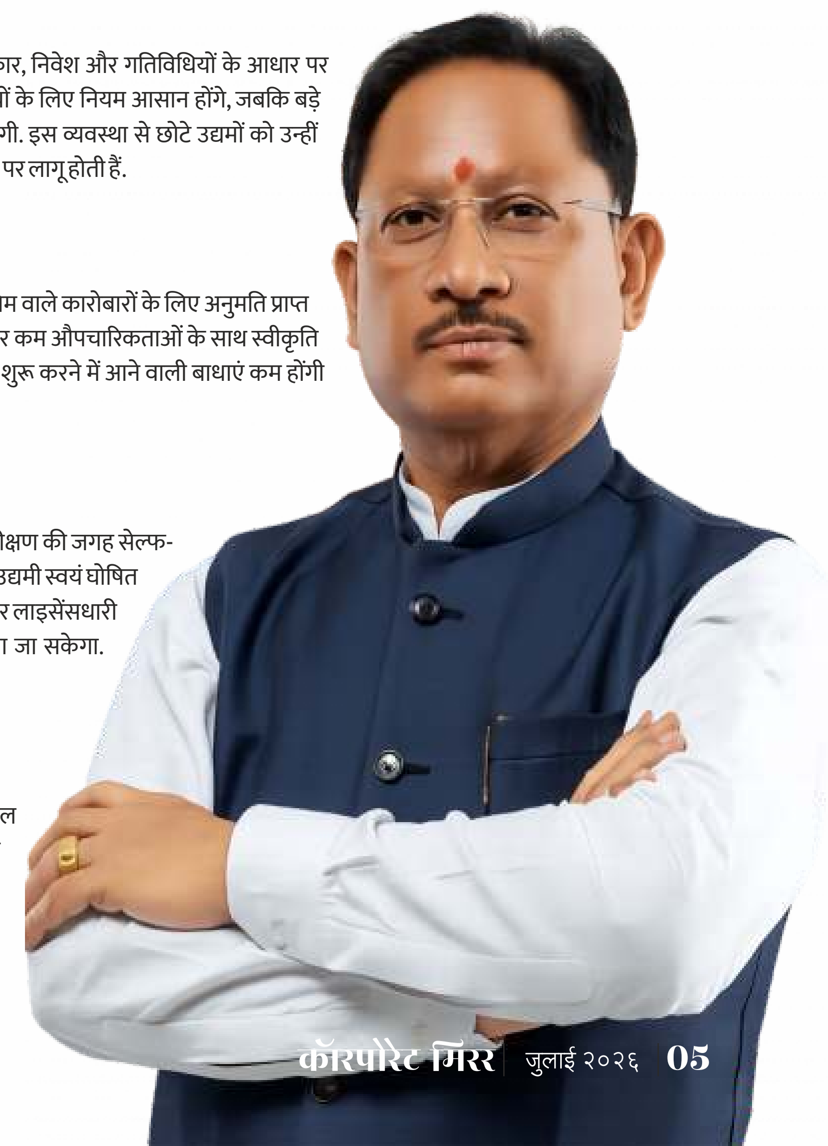

15 लाख से अधिक एमएसएमई और छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत

इस विधेयक के माध्यम से सरकार का मुख्य फोकस 15 लाख से अधिक एमएसएमई (MSMEs) और छोटे कारोबारियों को राहत देना है, जिन्हें अब हर साल लाइसेंस रिन्यू कराने और अनावश्यक विभागीय निरीक्षणों से मुक्ति मिलेगी। छत्तीसगढ़ के दूर-दराज के इलाकों, जैसे बस्तर और सरगुजा संभाग में चल रहे वनोपज आधारित लघु उद्योगों, हथकरघा और स्थानीय कुटीर उद्योगों को इस कानून से विशेष संबल मिलेगा। कागजी औपचारिकताएं कम होने से ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे उद्यमी बिना किसी कानूनी डर के अपने व्यापार का विस्तार कर सकेंगे। राज्य के विभिन्न चैंबर ऑफ कॉमर्स और कैट (CAIT) जैसे व्यापारिक संगठनों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। कारोबारियों का कहना है कि अनुपालन (Compliance) का बोझ कम होने से न केवल उनका समय और पैसा बचेगा, बल्कि वे अपने बिजनेस को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।

तय समय में नहीं मिला जवाब तो माना जाएगा अप्रूव

इस एक्ट का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि यदि कोई विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी आवेदन पर निर्णय नहीं लेता है, तो उसे डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा. इससे फाइलों के लंबे समय तक अटकने की समस्या कम होगी और निवेशकों को समय पर फैसले मिल सकेंगे. सरकार का उद्देश्य अनुमोदन प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाना है.

MSME को सबसे ज्यादा फायदा

राज्य में 15 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) इस कानून से लाभान्वित हो सकते हैं. पानी कनेक्शन, फर्म या सोसायटी पंजीकरण, बिल्डिंग प्लान मंजूरी जैसी कई सेवाओं को पहले से आसान और तेज बनाया जाएगा. उद्योग जगत का मानना है कि इससे नए निवेश आकर्षित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

8 विभागों की 43 सेवाएं होंगी शामिल

नया कानून फिलहाल 8 विभागों की 43 सेवाओं को इस सरल अनुमोदन व्यवस्था के तहत लाता है. भविष्य में आवश्यकता के अनुसार और सेवाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकेगा. सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं को डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है.

तीन स्तर पर होगी निगरानी

कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तीन स्तरीय निगरानी व्यवस्था बनाई गई है. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति काम करेगी, जबकि जिला स्तर पर कलेक्टर की अगुवाई में निगरानी तंत्र बनाया जाएगा. इन दोनों समितियों की गतिविधियों पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद की निगरानी रहेगी, ताकि तय समय में सभी प्रावधान लागू हो सकें.

“

यह राज्य में उद्योग और कारोबार को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, जहां इस तरह की जोखिम और विश्वास आधारित बिजनेस परमिशन व्यवस्था लागू की जा रही है। जटिलताओं का खात्मा: मुख्यमंत्री कार्यालय और सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पुरानी, जटिल और लंबी कागजी प्रक्रियाओं को पूरी तरह समाप्त कर उन्हें डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। इससे निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। युवाओं को रोजगार: इस नई नीति से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, औद्योगिक विकास तेज होगा और अंततः छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

-विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

इस कानून का उद्देश्य टुकड़ों में या अलग-अलग विभागीय बदलाव करने के बजाय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक मजबूत और व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करना है। एक साथ सभी विभागों में सुधार: उन्होंने कहा कि इस कानून की मदद से कई विभागों में एक साथ सुधार लागू किए जा सकेंगे, जिससे फाइलें अटकने की देरी खत्म होगी और सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में बड़ा सुधार आएगा। जागरूकता अभियान और लचीलापन: उद्योग मंत्री ने यह भी घोषणा की कि नियम (Rules) अधिसूचित होने के बाद सरकार उद्यमियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को इस नई प्रणाली से परिचित कराने के लिए राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। उन्होंने साफ किया कि भविष्य में नई सेवाओं को जोड़ने के लिए बार-बार नया कानून बनाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर अतिरिक्त सेवाओं को सीधे शामिल किया जा सकेगा।

लखनलाल देवांगन, उद्योग मंत्री, छत्तीसगढ़

आलेख

पीएम मित्र पार्क के ज़रिए बदल रही भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र की तस्वीर

पबित्रा मार्गेरिटा
केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री
भारत सरकार

सदियों से, भारत की पहचान उसके परिधानों से गहराई से जुड़ी रही है। चाहे वह कश्मीर के पश्मीना की लंबे समय तक रहने वाली गर्माहट हो, असम के मूंगा सिल्क की सुनहरी चमक हो, तमिलनाडु की शाही कांजीवरम साड़ियाँ हों, चंदेरी की बुनाई हो या सूरत के कारीगरों की कपड़ों पर मशहूर कारीगरी। आज भी यह क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा है, जो जीडीपी में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है। खेती के बाद भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला यह क्षेत्र 45 मिलियन लोगों को सीधे तौर पर और 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार देता है। इससे ग्रामीण समुदायों को मजबूती मिलती है और देश भर में लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक आज़ादी का रास्ता खुलता है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के एक साथ जुड़ी हुई व्यवस्था के उलट, भारत की वस्त्र मूल्य श्रृंखला ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग जगहों पर फैले हुए मॉडल के तौर पर विकसित हुई। कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग, कपड़े सिलने और निर्यात जैसी गतिविधियाँ अलग-अलग राज्यों में स्वतंत्र रूप से विकसित हुईं, जिसका अर्थ था कि एक कपड़ा बनने के दौरान अक्सर कई राज्यों की सीमाओं से गुज़रता था। इस बिखराव के कारण कई संरचनात्मक बाधाएँ पैदा हुईं। इसने बड़े पैमाने पर काम करने, आधुनिकीकरण, ऑटोमेशन और आखिरकार मज़दूरों की उत्पादकता को सीमित कर दिया। इसके साथ ही, मल्टी-मॉडल संपर्क में कमियों की वजह से लॉजिस्टिक्स का बोझ भी बढ़ जाता है। प्रोडक्शन के अलग-अलग चरणों के बीच हर बार सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या संभालने में अतिरिक्त खर्च और ढुलाई का किराया लगता है। कई चरणों में लंबी दूरी तक सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने से कुल लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ जाती है और सामान को तेज़ी से बाज़ार तक पहुँचाने की क्षमता खत्म हो जाती है, जो आज की रिटेल व्यवस्था में बार-बार ऑर्डर देने वाले साइकल में एक बहुत बड़ी और नुकसानदायक कमी है।

वर्तमान में पर्यावरण से जुड़ी ज़रूरतों पर भी ध्यान देने की ज़रुरत है। दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी 8% से 10% और औद्योगिक जल प्रदूषण में 20% है। हज़ारों छोटी-छोटी और अलग-अलग जगहों पर फैली इकाइयों में नियमों को लागू करना और सही तरीके से प्रबंधन करना पहले एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती रहा है। इन रुकावटों को व्यवस्थित रूप से दूर करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) योजना शुरू की, जिसके लिए ₹4,445 करोड़ का बजट रखा गया। यह एक अहम कदम था, जो एक ऐसा व्यापक मॉडल पेश करता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों से जुड़े लोगों और निजी साझेदारों के साथ मिलकर विकास को आगे बढ़ाती है।

इस योजना के केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी '5एफ' फ़ॉर्मूला है यानी फ़ार्म (खेत) से फ़ाइबर (रेशा) से फ़ैक्टरी (कारखाना) से फ़ैशन और फारेन (विदेश) तक पहुंच। यह सोच सीधे तौर पर उस बात को सामने लाती है, जो भारत को वैश्विक मंच पर अलग बनाती है: हमारी संपूर्ण और बेहद विविध मूल्य श्रंखला। कच्चे माल के आयात या सिर्फ तैयार कपड़ों की बनावट पर निर्भर रहने वाले दूसरे देशों के उलट, भारत वस्त्रों को बनाने की पूरी प्रक्रिया में शामिल है, जिसमें किसानों के खेतों से लेकर हाई-फ़ैशन रनवे तक की प्रक्रिया शामिल है। इस अनोखी समझ की वजह से, हमारी विकास रणनीति को वैश्विक प्रतिस्पर्धा और पूरी तरह से सामाजिक समानता के बीच एक खास संतुलन बनाने की ज़रुरत है। विस्तार करते समय, हमें हर क्षेत्र के कल्याण का ध्यान रखना होगा, ताकि साधारण किसान और ग्रामीण बुनकर से लेकर कपड़े के निर्यातक तक, कोई भी पीछे न छूटे। पीएम मित्र फ़्रेमवर्क इसी संतुलन को हासिल करता है।

इन पार्कों को कच्चे माल के मुख्य केंद्रों के पास रणनीतिक रूप से बनाने से ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होता है और निर्माण के लिए बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इससे ज़रूरी बात यह है कि इस नज़दीकी से शुरुआत से आखिर तक ट्रैकिंग भी मुमकिन हो पाती है। चूँकि वैश्विक ब्रांड ऑर्गेनिक या सस्टेनेबल प्रमाणीकरण की मांग करते हैं, इसलिए ये एकीकृत पार्क एक सत्यापन योग्य कस्टडी चेन देते हैं। इससे कड़े वैश्विक ईएसजी नियमों का पालन होता है और विदेशों में प्रीमियम कीमत पाने का रास्ता भी बनता है। 1,000 एकड़ से ज़्यादा के एक ही इलाके में कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग और कपड़ा बनाने की सुविधाओं को एक साथ लाने से अलग-अलग राज्यों के बीच सामान ले जाने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। इससे माल ढुलाई का खर्च और ट्रांसपोर्ट से होने वाला प्रदूषण भी बहुत कम हो जाता है और सामान तेज़ी से बाज़ार तक पहुँच पाता है। समर्पित माल गलियारे और एक्सप्रेसवे जैसे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर से जुड़े होने के कारण, विदेशी बाज़ारों तक सामान पहुँचाना बहुत सस्ता और किफायती हो जाता है। हर पार्क में 'प्लग-एंड-प्ले' इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें बिजली के खास सब-स्टेशन, लगातार पानी की सप्लाई और तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार फैक्ट्री शेड जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इसके साथ ही, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ज़ेडएलडी) तकनीक वाले उन्नत एडवांस्ड कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और आधुनिक सुविधाएँ भी होती हैं, जिससे कारोबारियों पर ढांचागत बोझ कम पड़ता है और कारोबार करने में आसानी होती है।

पीएम मित्र पार्क तेज़ी से कागज़ी योजनाओं को असल ज़मीनी हकीकत में बदल रहे हैं। इस योजना में सात रणनीतिक पार्क शामिल हैं: पाँच ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट विरुधुनगर (तमिलनाडु), नवसारी (गुजरात), कलबुर्गी (कर्नाटक), धार (मध्य प्रदेश) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और दो ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट वारंगल (तेलंगाना) और अमरावती (महाराष्ट्र) में। अब तक, इस योजना में कुल ₹69,899 करोड़ के निवेश की दिलचस्पी दिखाई गई है, जिसमें से ₹27,658 करोड़ का निवेश पहले ही हो चुका है। 10 मई, 2026 को माननीय प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के वारंगल में पहले कार्यरत पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क में पहले ही ₹3,862 करोड़ का निवेश हो चुका है और यहाँ विश्व-स्तरीय पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढ़ांचे पर काम किया जा रहा है। ये विशेषताएँ स्थायित्व के उन मानकों को दर्शाती हैं, जिन्हें सभी सात पार्क साइटों पर स्थापित किया जा रहा है।

पूरे देश में एक साथ काम शुरू होने से सहकारी संघवाद की तेज़ी और सफलता दोनों साफ दिखती है, जहां सभी सात राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, 100% ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है और पर्यावरण से जुड़ी मंज़ूरी भी मिल गई है। पाँच ग्रीनफ़ील्ड साइट्स के लिए जेवी एग्रीमेंट और एसपीवी पूरी तरह से तैयार हैं, जिससे तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। 2,158 एकड़ में फैले सबसे बड़े पार्क, धार (मध्य प्रदेश) में ₹21,436.9 करोड़ के निवेश में दिलचस्पी दिखाई गई है। इसी तरह गुजरात (₹13,084 करोड़), महाराष्ट्र (₹12,925 करोड़), तमिलनाडु (₹6,600 करोड़), उत्तर प्रदेश (₹5,345.8 करोड़) और कर्नाटक (₹1,700 करोड़) में भी काम को लेकर तेज़ी देखी गई है। तेज़ी से हो रहे इस काम के पीछे केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह का सक्रिय नेतृत्व है। उनके कुशल नेतृत्व में वस्त्र मंत्रालय अपने कामकाज के तरीकों में तेज़ी लाया है, मंत्रालय ने प्रशासनिक रुकावटों को दूर किया है और राज्य सरकारों के साथ अभूतपूर्व स्तर पर आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया है।

लेकिन आंकड़े तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं, असली पैमाना इसके मानवीय प्रभाव में दिखता है। प्रत्येक पार्क को संरचनात्मक रूप से इस प्रकार तैयार किया गया है कि इससे लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यानी सभी सात स्थलों को मिलाकर, 21 लाख से अधिक औपचारिक आजीविकाएं हैं, जो हमारे ग्रामीण परिवारों और महिलाओं को अहम सामाजिक-आर्थिक नींव प्रदान करती हैं, जो पारंपरिक रूप से परिधान निर्माण उद्योग की रीढ़ हैं।

यह व्यापक ढ़ांचागत प्रयास वस्त्र क्षेत्र के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण 2030 के लिए एक अहम लॉन्चपैड का काम करता है, जिसका लक्ष्य इस दशक के अंत तक भारत के वस्त्र उद्योग को 350 बिलियन डॉलर की वैश्विक महाशक्ति में बदलना है। ऐतिहासिक विखंडन को विश्व स्तरीय, एकीकृत पैमाने से बदलकर करके, पीएम मित्र एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन ला रहा है। सशक्त नेतृत्व के मार्गदर्शन में, हम भारत को वस्त्रों के निर्विवाद, टिकाऊ और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी केंद्र के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। (स्त्रोतः पीआईबी)

आलेख

स्वच्छ ऊर्जा: विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति का मार्ग

श्रीपद नाइक
विद्युत राज्यमंत्री
भारत सरकार

वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता, ऊर्जा की बढ़ती मांग और जलवायु से जुड़ी गंभीर चुनौतियों के इस दौर में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ऐसी ऊर्जा प्रणालियों का निर्माण करने की जरूरत है जो स्वच्छ व अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित, सस्ती एवं भरोसेमंद होने के साथ-साथ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास संबंधी जरूरतों तथा आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप भी हों। स्वच्छ ऊर्जा दरअसल ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से तेजी से अहम होती जा रही है। यह ईंधन बाजार में आने वाले उतार-चढ़ाव से पैदा होने वाले जोखिमों को कम कर सकती है, ऊर्जा को अपेक्षाकृत अधिक सुलभ बना सकती है, रोजगार सृजित कर सकती है, घरेलू उद्योगों को मजबूत कर सकती है और देश को अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ बना सकती है।

इसी बिंदु पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच आपसी सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच बेहतर सहयोग से स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समावेशी विकास के साझा लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत का अपना अनुभव यह बताता है कि स्वच्छ ऊर्जा की शुरुआत लोगों से ही होनी चाहिए।

पिछले दशक में, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत लगभग 28.6 मिलियन घरों को बिजली के कनेक्शन दिए गए। इससे सभी तक बिजली पहुंचाने का काम आगे बढ़ा और ग्रामीण व कम सुविधा वाले इलाकों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत महिलाओं को 105 मिलियन से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इससे खाना पकाने के साफ-सुथरे तरीकों को बढ़ावा मिला, घर में सेहत बेहतर हुई और कठिन श्रम का बोझ कम हुआ।

ये पहल एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करती हैं: स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने को केवल स्थापित मेगावाट या जोड़ी गई क्षमता के आधार पर नहीं मापा जा सकता, बल्कि इससे पैदा हुए अवसरों, सुदृढ़ हुई आजीविका और बेहतर हुए जीवन स्तर के आधार पर भी मापा जाना चाहिए।

लोगों को प्राथमिकता देने वाले इस दृष्टिकोण के साथ-साथ बड़े पैमाने पर काम और सहयोगी बुनियादी ढांचे की भी जरूरत है। भारत की स्वच्छ ऊर्जा की कहानी में नवीकरणीय ऊर्जा अहम हो गई है। लेकिन इसकी सफलता इसे समर्थन प्रदान करने वाली प्रणालियों पर निर्भर करती है। सौर और पवन ऊर्जा को तेजी से अपनाया जा सकता है, लेकिन इनकी पूरी क्षमता का लाभ तभी मिल पाएगा जब पारेषण (ट्रांसमिशन), वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन), भंडारण (स्टोरेज) और ग्रिड प्रबंधन एकसाथ मिलकर काम करें।

भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में सहायता प्रदान करने वाली प्रणालियों को मजबूत करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। पारेषण संबंधी बुनियादी ढांचे (ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर) का निरंतर विस्तार हुआ है। इसके साथ-साथ ऊर्जा के भंडारण (एनर्जी स्टोरेज) और ग्रिड की सुदृढ़ता (ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी) के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा है। वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) संबंधी सुधारों और उन्नत ग्रिड तकनीक को अपनाने से एक ऐसी बेहतर एवं भरोसेमंद ऊर्जा प्रणाली बनाने में मदद मिली है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी को समन्वित करने में सक्षम है।

भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन पर आधारित क्षमता अब 288 गीगावॉट से अधिक हो गई है। बड़े पैमाने की परियोजनाओं के अलावा, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) प्रणालियां – जैसे कि रूफटॉप सोलर, सोलर पंप, मिनी-ग्रिड और माइक्रो-ग्रिड – ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में स्वच्छ ऊर्जा को और अधिक सुलभ बना रही हैं। ये प्रणालियां सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज, स्कूलों, हेल्थकेयर सेंटरों तथा स्थानीय व्यवसायों को मदद पहुंचाने के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका और स्थानीय आर्थिक सुदृढ़ता को भी बढ़ावा दे रही हैं।

भारत की 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' बड़े पैमाने पर इस दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस योजना से अब तक लगभग 4 मिलियन परिवारों को लाभ हुआ है, जिससे उपभोक्ता अपेक्षाकृत अधिक विकेन्द्रीकृत एवं भागीदारी वाली ऊर्जा प्रणाली में योगदान देने वाले बन पाए हैं।

हालांकि, स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में वित्त पोषण सबसे अहम तत्वों में से एक बना रहेगा। कई विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने तथा बैंक से ऋण पाने योग्य परियोजनाओं में बदलने हेतु सस्ती और दीर्घकालिक पूंजी की जरूरत होती है।

आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा, वितरण संबंधी बुनियादी ढांचा, ग्रिड के आधुनिकीकरण, भंडारण प्रणाली और कम ऊर्जा खर्च करने वाली तकनीकों में निवेश बेहद जरूरी होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थान वित्त पोषण, तकनीक संबंधी साझेदारी और क्षमता विकास के जरिए विकासशील देशों की मदद करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी तकनीकों के लिए सुदृढ़ एवं विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखला बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सुरक्षित, सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा प्रणालियां सुनिश्चित करने हेतु मैन्यूफैक्चरिंग, तकनीक, नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना जरूरी होगा। अब जबकि ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता आगे बढ़ रही है, सहयोग की एक ऐसी भविष्योन्मुखी रूपरेखा को मजबूत करने का अवसर है जो सामर्थ्य, बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता, विश्वसनीयता, तकनीक की सुलभता, सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला और सतत विकास का समर्थन करे।

चुनौती सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने की ही नहीं, बल्कि ऐसे ऊर्जा प्रणाली के निर्माण की भी है जो सबके लिए सुलभ, किफायती एवं भरोसेमंद होने के साथ-साथ दीर्घकालिक आर्थिक विकास और मानव विकास को कायम रखने में सक्षम हों। (स्त्रोतः पीआईबी)

संपत्ति में बढ़ी महिलाओं की भागीदारी

पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट का दिख रहा सकारात्मक प्रभाव

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और संपत्ति स्वामित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट की पहल के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। विभाग द्वारा 06 मई 2026 से 30 जून 2026 की अवधि का पिछले वर्ष की समान अवधि से तुलनात्मक विश्लेषण करने पर पाया गया कि वर्ष 2025 में महिलाओं के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेखों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2026 में बढ़कर 41 प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि में महिलाओं के नाम पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या 14,668 से बढ़कर 21,292 हो गई, जो लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।

राज्य के लगभग 75 प्रतिशत जिलों में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में 20 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। जांजगीर-चांपा, बलोद, कोरिया, रायपुर तथा कांकेर सहित अनेक जिलों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। महिलाओं को प्रदान की गई पंजीयन शुल्क में छूट के परिणामस्वरूप इस अवधि में नागरिकों को लगभग 50.14 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है। इससे न केवल महिलाओं के नाम पर संपत्ति स्वामित्व को बढ़ावा मिला है, बल्कि परिवारों को भी आर्थिक राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन को प्रोत्साहित करने के लिए पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का निर्णय इसी सोच का परिणाम है। संपत्ति पर महिलाओं का स्वामित्व उन्हें आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ परिवार और समाज में अधिक सम्मान भी प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में परिवार लाभान्वित हुए हैं और महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारी सरकार ऐसी नीतियों को लगातार बढ़ावा दे रही है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकास यात्रा की समान भागीदार बनाएं। मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में हुई यह उल्लेखनीय वृद्धि केवल एक सांख्यिकीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का संकेत है। जब किसी महिला के नाम संपत्ति होती है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, परिवार में उसकी निर्णयात्मक भूमिका सुदृढ़ होती है और आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को विकास प्रक्रिया के केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट का उद्देश्य केवल आर्थिक राहत देना नहीं, बल्कि महिलाओं को संपत्ति स्वामित्व से जोड़कर उन्हें वास्तविक अर्थों में सशक्त बनाना है। प्रारंभिक परिणाम बताते हैं कि यह पहल अपने उद्देश्य की दिशा में प्रभावी सिद्ध हो रही है। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी एवं समावेशी पंजीयन व्यवस्था के निर्माण के लिए निरंतर सुधार कर रही है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा किए जा रहे सुधारों एवं प्रोत्साहनात्मक उपायों का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना तथा शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है।

51,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं से देश का नया 'लॉजिस्टिक्स हब' बनता छत्तीसगढ़

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से पिछले ढाई वर्षों में रेलवे अधोसंरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। रिकॉर्ड बजटीय निवेश, नई रेल लाइनों का निर्माण, मल्टी-ट्रैकिंग, दोहरीकरण, आधुनिक स्टेशन, शत-प्रतिशत विद्युतीकरण तथा दूरस्थ आदिवासी अंचलों तक रेल संपर्क के विस्तार ने छत्तीसगढ़ को देश के रेलवे मानचित्र पर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। वर्तमान में प्रदेश में ₹51 हजार करोड़ से अधिक लागत की रेल परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, जो राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा रेलवे निवेश है और विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत आधारशिला बन रहा है।

रेलवे क्षेत्र में हुआ रिकॉर्ड निवेश इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण है। वर्ष 2014 से पहले छत्तीसगढ़ को रेल परियोजनाओं के लिए औसतन लगभग ₹300 करोड़ का वार्षिक बजट प्राप्त होता था, जबकि वर्ष 2026-27 में यह बढ़कर ₹7,470 करोड़ तक पहुंच गया है। अर्थात एक दशक में रेलवे बजट में लगभग 24 गुना की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। यह केवल बजट में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के प्रति केंद्र सरकार की विकास प्राथमिकताओं और राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता का परिचायक है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास को अभूतपूर्व गति दी है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की पहल पर जिस तेजी से नई रेल परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है और उन पर कार्य प्रारंभ हुआ है, उसने प्रदेश के विकास की दिशा ही बदल दी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य और मध्य भारत का महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स केंद्र है। ऐसे में मजबूत रेल नेटवर्क प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। रेलवे विकास से उद्योगों की परिवहन लागत कम होगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होंगे तथा युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित होंगे। दूरस्थ वनांचलों तक रेल पहुंचने से विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र को आधुनिक रेल नेटवर्क से जोड़ना है। बस्तर, सरगुजा, जशपुर और अन्य दूरस्थ अंचलों में रेलवे पहुंचने से विकास का दायरा और व्यापक होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे अब केवल यात्रियों और माल परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन बन चुकी है। विकसित भारत-2047 के संकल्प के अनुरूप हम छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी रेल एवं लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री के इस विज़न को साकार करने की दिशा में प्रदेश में अनेक महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। रेल नेटवर्क के विस्तार में भी छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 1853 से 2014 तक लगभग 161 वर्षों में जहां राज्य में करीब 1,100 रूट किलोमीटर रेल नेटवर्क विकसित हुआ था, वहीं अब छत्तीसगढ़ का रेल नेटवर्क 2,200 रूट किलोमीटर से अधिक करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। लगभग 1,200 किलोमीटर नए रेल ट्रैक, शत-प्रतिशत रेल विद्युतीकरण, अत्याधुनिक सिग्नलिंग व्यवस्था तथा मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं ने रेलवे परिचालन को अधिक सुरक्षित, तेज and ऊर्जा दक्ष बनाया है।

बस्तर अंचल में रावघाट रेल परियोजना विकास की नई धुरी बनकर उभरी है। दल्लीराजहरा से अंतागढ़ तक 77 किलोमीटर रेलखंड पर यात्री रेल सेवा प्रारंभ होने से हजारों ग्रामीण पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़े हैं। परियोजना के अगले चरण में तुमापाल (ताहोकी) से कोसरोण्डा तक पुल-पुलियों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है तथा रेल लाइन बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है। कोसरोण्डा से रावघाट तक रेलवे अधोसंरचना का निर्माण भी अंतिम चरण में है। परियोजना पूर्ण होने पर रावघाट की लौह अयस्क खदानें सीधे भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़ जाएंगी, जिससे उद्योगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को नई मजबूती मिलेगी। वहीं कोत्तावलसा-किरंदुल रेल लाइन के दोहरीकरण से बस्तर क्षेत्र में माल एवं यात्री परिवहन की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

विकासगाथा

धमतरी में औद्योगिकीकरण की नई दिशा

कुरूद तहसील के ग्राम बगौद में स्थित मेगा फूड पार्क में स्थापित हुए 13 उद्योग, 63.84 करोड़ का निवेश

चंदन शर्मा
धमतरी ब्यूरो चीफ

कॉरपोरेट मिरर रिपोर्ट

धमतरी। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला अपनी भौगोलिक स्थिति, कृषि संपन्नता और संसाधनों की प्रचुरता के कारण औद्योगिक मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। राजधानी रायपुर और औद्योगिक नगरी दुर्ग-भिलाई के निकट होने से यह जिला निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के लिए अत्यंत उपयुक्त सिद्ध हो रहा है। शासन और प्रशासन के ठोस प्रयासों के चलते जिले में औद्योगिकीकरण की नई लहर दिखाई दे रही है। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं बल्कि जिले की आर्थिक प्रगति को भी नई गति मिल रही है।

मुख्यमंत्री की पहल और औद्योगिक क्षेत्र का विकास

हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा धमतरी जिले के करेली बड़ी और भालूझूलन में फूड पार्क का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। यह फूड पार्क कृषि आधारित उद्योगों को नई दिशा प्रदान करेगा तथा किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त करेली बड़ी, भालूझूलन और जामगांव में औद्योगिक क्लस्टरों का विकास किया गया है। ये स्थल रायपुर से अत्यंत निकट होने के कारण निवेशकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। धमतरी जिले में पाँच औद्योगिक क्लस्टरों की योजना है। इनमें से तीन क्लस्टरों का लोकार्पण हो चुका है तथा शेष का भूमिपूजन शीघ्र ही किया जाएगा। इन क्लस्टरों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को मजबूती मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होगा।

मेगा फूड पार्कों की संभावनाएँ

धान की प्रचुर उपज के कारण धमतरी को "धान का कटोरा" कहा जाता है। जिले में धान से संबंधित उद्योगों जैसे राइस मिल, चावल आधारित प्रसंस्कृत उत्पाद, पैकेजिंग इकाइयाँ और बाय-प्रोडक्ट उद्योगों की अपार संभावनाएँ हैं। इसी दृष्टि से शासन द्वारा छाती और कचना में मेगा फूड पार्क की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। विशेष रूप से छाती क्षेत्र का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इसके स्वीकृत होने पर जिले की औद्योगिक संरचना और अधिक सुदृढ़ होगी। इन मेगा फूड पार्कों में धान, सब्जी, दलहन और अन्य कृषि उत्पादों का वैज्ञानिक एवं आधुनिक तकनीक से प्रसंस्करण किया जाएगा। तैयार उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने की योजना है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और जिले की आर्थिक स्थिति और मजबूत बनेगी।

प्रशासन की सक्रियता और कलेक्टर की भूमिका

जिले में औद्योगिकीकरण को गति देने में प्रशासन की भूमिका उल्लेखनीय है। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा स्वयं औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत् निगरानी रख रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है तथा निवेशकों को आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। श्री मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे हों। वर्तमान में मेगा फूड पार्क बगौद (तहसील कुरूद) में औद्योगिक भूमि का आबंटन किया जा रहा है। यहाँ अब तक 13 उद्योग उत्पादन में आ चुके हैं, जिनमें 63.84 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और 236 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा 25 उद्योग निर्माणाधीन हैं, जिनमें 116.59 करोड़ रुपये का निवेश एवं 446 रोजगार प्रस्तावित हैं।

हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम करेलीबड़ी (तहसील मगरलोड) और ग्राम भालूझूलन (तहसील कुरूद) में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु क्रमशः 14.00 हेक्टेयर एवं 11.00 हेक्टेयर भूमि पर कुल 19.38 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इसी प्रकार ग्राम जामगांव (तहसील कुरूद) में 10.00 हेक्टेयर भूमि पर 6.43 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण पूरा किया गया है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।

इसके अतिरिक्त ग्राम छाती (तहसील धमतरी) एवं ग्राम कचना (तहसील भखारा) में क्रमशः 18.21 हेक्टेयर एवं 8.42 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक लैण्ड बैंक हेतु हस्तांतरित की गई है। छाती क्षेत्र एनएच-30 से लगा हुआ है तथा कचना धमतरी-रायपुर मार्ग पर रायपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं ग्राम श्यामतराई (तहसील धमतरी) में 8.83 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, जिसका लोकार्पण शीघ्र किया जाएगा। इसके अलावा लगभग 90 हेक्टेयर भूमि पर पाँच अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की तैयारी की जा रही है। यह पूरा विकास कार्य रायपुर-धमतरी इकोनामिक कॉरिडोर के रूप में आकार ले रहा है।

भविष्य की संभावनाएँ

धमतरी की भौगोलिक स्थिति, कृषि संसाधन और रायपुर से निकटता इसे निवेश के लिए आदर्श स्थल बना रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योगों, MSME इकाइयों और बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना से जिले का औद्योगिक स्वरूप और अधिक विकसित होगा। धमतरी का औद्योगिकीकरण न केवल स्थानीय स्तर पर आर्थिक दशा को बदलने वाला है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ एवं देश के औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की सक्रियता से जिले में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। कृषि और उद्योग के संगम से धमतरी का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। आने वाले समय में धमतरी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास की धुरी बनेगा।

पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरा

यूरेनियम डील समेत 18 समझौतों से इंडो-पैसिफिक में बदलेगा पावर बैलेंस

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन में 18 बड़े समझौते हुए हैं। इनमें सबसे अहम फैसला सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को ऑपरेशनल करना है, जिससे अब भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम एक्सपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी दोनों देशों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज की इस रणनीतिक मुलाकात ने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई दी है।

रक्षा क्षेत्र में दो बड़े समझौतों पर लगी मुहर

इस समिट में रक्षा और सुरक्षा के लिहाज से दो सबसे महत्वपूर्ण आउटकम सामने आए हैं:

- इंडिया-ऑस्ट्रेलिया जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन (JDDSC)
- इंडिया-ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप (MSCR)
- विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक स्पेशल मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि ये दोनों समझौते बदलते भू-राजनीतिक (Geopolitical) हालातों के हिसाब से बेहद जरूरी हैं।
- JDDSC का दायरा: यह 2009 के पुराने डिक्लेरेशन को और विस्तार देता है। इसमें डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर-टेररिज्म और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (Emerging Tech) पर खास फोकस रहेगा।

इंडो-पैसिफिक की सुरक्षा और UNCLOS पर जोर

पीएम मोदी और एंथनी अल्बनीज ने एक खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) क्षेत्र के साझा विजन को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने इलाके में बढ़ती अनिश्चितता पर चिंता व्यक्त की।

"क्षेत्र में किसी भी विवाद को ताकत या दबाव के बिना, अंतरराष्ट्रीय कानून (UNCLOS) के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। संप्रभुता (Sovereignty) और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सर्वोपरि है।"

सेनाओं के बीच बढ़ेगा तालमेल, तैनात होंगे भारतीय मिलिट्री इंस्ट्रक्टर

दोनों देशों ने अपनी सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी (Interoperability) बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए हैं:

सैन्य अभ्यास: दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज अब और ज्यादा जटिल और व्यापक होंगी।

एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट: एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों से एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया जाएगा।

मिलिट्री ट्रेनिंग: साल 2028-29 में भारतीय मिलिट्री इंस्ट्रक्टर ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस कॉलेज में तैनात किए जाएंगे।

एनुअल डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग: दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच अब हर साल आधिकारिक बातचीत होगी।

समुद्री सुरक्षा के लिए मजबूत रोडमैप

समुद्री क्षेत्र की भूमिका को देखते हुए मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप को अपनाया गया है। यह रोडमैप रियल-टाइम सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को मजबूत करेगा। इसके अलावा, भारत के कोस्ट गार्ड और ऑस्ट्रेलिया के मैरीटाइम बॉर्डर कमांड के बीच एक MoU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद और PACTS पर फैसले

सुरक्षा का यह सहयोग सिर्फ जमीन और समुद्र तक सीमित नहीं है। यह अब साइबर स्पेस तक फैल चुका है:

PACTS फ्रेमवर्क: 'ऑस्ट्रेलिया-इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स' के तहत दोनों देश मिलकर काम करेंगे।

आतंकवाद पर प्रहार: ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को रोकने, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए खुफिया जानकारी साझा की जाएगी।

आपदा राहत (HADR): क्वाड इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के जरिए दोनों देश आपदा प्रबंधन में एक-दूसरे की मदद करेंगे।

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को मिली हरी झंडी

भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक रेलवे तकनीक की दिशा में एक नया कदम बढ़ाते हुए अपनी पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत कर दी है. पीएम नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद में इस ट्रेन का शुभारंभ किया है. वहीं इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे देश के लिए एक ऐतिहासिक तकनीकी उपलब्धि बताया है और कहा कि अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन विकसित करने की पूरी तकनीक मौजूद है. आइए जानते हैं डिटेल्स.

भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत

नई ट्रेन के लॉन्च के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह उपलब्धि देश में विकसित हो रही स्वदेशी तकनीक और इनोवेशन का परिणाम है. उन्होंने कहा कि भारत ने हाइड्रोजन तकनीक विकसित करने में बड़ी सफलता हासिल की है और अब देश के पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन तैयार करने की पूरी क्षमता मौजूद है. इसी के साथ साथ रेल मंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देते हुए कहा कि उनके विजन की वजह से भारत नई तकनीकों में तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश आज केवल नई तकनीक अपनाने वाला नहीं, बल्कि उसे विकसित करने वाला देश बन रहा है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस अवसर को राज्य और देश के लिए ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होना हरियाणा के लिए गर्व की बात है और यह भारत के विकास सफर में एक नया अध्याय जोड़ता है. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना केवल एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं है, बल्कि क्लीन एनर्जी, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने वाला कदम है. इस परियोजना के जरिए हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन, स्टोरेज, रीफ्यूलिंग, संचालन और रखरखाव से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है. इससे भविष्य में हाइड्रोजन आधारित रेल सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

अगले साल से भारत में आ सकते हैं प्लास्टिक के नोट

भारतीय करेंसी में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारत में जल्द ही प्लास्टिक यानी पॉलीमर के नोट देखने को मिल सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI जल्द ही देश में पॉलीमर बैंक नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है. अगर शुरुआती ट्रायल सफल रहता है, तो साल 2027 से इन नए नोटों को चरणबद्ध तरीके से बाजार में उतारा जा सकता है. हालांकि, इससे मौजूदा कागज के नोट बंद नहीं होंगे. दोनों तरह की करेंसी कुछ समय तक साथ-साथ चलती रहेगी.

भारत में जल्द आएंगे 10 और 20 रुपये के पॉलीमर बैंक नोट

रिपोर्ट्स के अनुसार, RBI सबसे पहले 10 रुपये और 20 रुपये के पॉलीमर नोटों का सीमित स्तर पर ट्रायल करेगा. इस पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों का मूल्यांकन करने के बाद ही बड़े स्तर पर इन्हें जारी करने का फैसला लिया जाएगा. बता दें कि RBI का उद्देश्य यह समझना है कि भारतीय मौसम, इस्तेमाल और बाजार की परिस्थितियों में ये नोट कितने प्रभावी साबित होते हैं.

क्या होते हैं पॉलीमर बैंक नोट?

पॉलीमर बैंक नोट खास तरह की मजबूत प्लास्टिक जैसी चीज से तैयार किए जाते हैं. यह सामान्य कागजी नोटों की तुलना में कहीं अधिक टिकाऊ होते हैं. अक्सर जेब में रखे-रखे या बार-बार इस्तेमाल होने से नोट फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं या नमी से खराब हो जाते हैं. पॉलीमर नोटों में ऐसी दिक्कतें काफी कम होती हैं. यही वजह है कि कई देशों ने इन्हें अपनाया है. अब भारत भी ऐसे ही नोटों को अपनाने की तैयारी कर रहा है. इसके अलावा पॉलीमर नोटों में आधुनिक सुरक्षा फीचर्स जोड़ना आसान होता है. इससे नकली नोट तैयार करना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन हो जाता है. ऐसे में पॉलीमर बैंक नोट के आने से नकली करेंसी पर भी रोक लग सकती है.

पॉलीमर नोटों के लिए RBI की तैयारी

पॉलीमर नोटों की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए RBI की नोट छापने वाली यूनिट ने दुनिया भर की कंपनियों से विशेष पॉलीमर शीट की आपूर्ति के लिए आवेदन मांगे हैं. इन्हीं शीट्स पर नए नोट छापे जाएंगे. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे कई देशों में पॉलीमर नोट कई सालों से पहले से ही चल रहे हैं. इन देशों का अनुभव बताता है कि यह नोट ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं और जल्दी खराब नहीं होते.

ग्लोबल ट्रैवल एसोसिएशन अब छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा, पदाधिकारियों ने दी बधाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बढ़ते कुनबे में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। प्रदेश के प्रतिष्ठित 'ग्लोबल ट्रैवल एसोसिएशन' ने अब आधिकारिक रूप से चेम्बर की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसे व्यापारिक जगत में चेम्बर के प्रति बढ़ते विश्वास और उसकी मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। चेम्बर के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने ग्लोबल ट्रैवल एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष मनीष जैन, महामंत्री शुभम अग्रवाल और कोषाध्यक्ष राहुल वासवानी को चेम्बर परिवार में शामिल होने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चेम्बर लगातार व्यापारियों की आवाज को शासन-प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठा रहा है। व्यापार संचालन में आने वाली हर तकनीकी और व्यावहारिक परेशानी को दूर करने के लिए चेम्बर निरंतर प्रयासरत है, यही वजह है कि आज प्रदेश भर के विभिन्न व्यापारिक संघ लगातार इससे जुड़ रहे हैं।

इस अवसर पर मुख्य रूप से सलाहकार गुरजीत सिंह संधू, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी, कार्यकारी महामंत्री विकास आहूजा, उपाध्यक्ष दिलीप इसरानी, मनीष प्रजापति, अमरदास खट्टर, जितेंद्र शादीजा, तथा मंत्री राहुल खूबचंदानी और आकाश डुडानी सहित एसोसिएशन के सदस्य एवं चेम्बर के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। चेम्बर परिवार ने ग्लोबल ट्रैवल एसोसिएशन का आत्मीय स्वागत करते हुए भविष्य में मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया।

ट्रेड लाइसेंस में वर्गफुट शुल्क का विरोध, सीएम को ज्ञापन

रायपुर। प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में चेम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भेंट कर "छत्तीसगढ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025" में लागू वर्गफुट (स्क्वायर फीट) आधारित पंजीकरण शुल्क व्यवस्था को समाप्त करने तथा इसके स्थान पर न्यायसंगत लाइसेंसवार फ्लैट शुल्क प्रणाली लागू करने की मांग करते हुए विस्तृत ज्ञापन सौंपा। चेम्बर ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सरकार द्वारा 43 प्रमुख व्यवसायों को ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त करने का निर्णय स्वागतयोग्य है और इससे प्रक्रियागत सरलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन नियम-18 के तहत लागू वर्गफुट आधारित वार्षिक पंजीकरण शुल्क व्यापारियों के लिए राहत नहीं, बल्कि अतिरिक्त आर्थिक बोझ बनकर सामने आया है। नगर निगम क्षेत्रों में ₹6 प्रति वर्गफुट की दर से अधिकतम ₹30 हजार तक वार्षिक शुल्क निर्धारित किए जाने से विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यापारी प्रभावित होंगे।

चेम्बर ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को केवल उठाना ही नहीं, बल्कि उनका व्यावहारिक समाधान सरकार तक पहुँचाना संगठन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ प्रदेशभर से प्राप्त सुझावों और व्यापारियों की चिंताओं का अध्ययन कर यह मांगपत्र तैयार किया गया है। चेम्बर का उद्देश्य किसी निर्णय का विरोध करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराना है जिससे व्यापार सरल हो और व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।

युवा कैट की मासिक बिजनेस मीट में गूंजा 'Connect, Collaborate, Grow' का मंत्र

रायपुर। युवा कैट रायपुर द्वारा आयोजित मासिक बिजनेस मीट का आयोजन तेलीबांधा स्थित होटल किंगवे में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों, उद्यमियों और प्रोफेशनल्स को एक साझा मंच उपलब्ध कराना था, जहां वे आपसी परिचय बढ़ाने, व्यावसायिक अनुभव साझा करने, नए व्यापारिक अवसर तलाशने और मजबूत नेटवर्किंग के माध्यम से अपने कारोबार का विस्तार कर सकें।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) सरदार अमरजीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी दौर में सफलता का सबसे बड़ा आधार मजबूत नेटवर्किंग, आपसी विश्वास और सहयोग है। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों से एक-दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि संगठित व्यापार ही प्रदेश की आर्थिक प्रगति की मजबूत नींव है। उन्होंने युवा कैट की इस पहल को व्यापारिक समुदाय के लिए प्रेरणादायी बताया। बिजनेस मीट में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने अपने-अपने व्यवसाय का परिचय देते हुए नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित किए और व्यापार विस्तार, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राहक सेवा, बिजनेस रेफरल तथा आधुनिक व्यावसायिक रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया। युवा कैट के प्रदेश अध्यक्ष कान्ति पटेल और प्रदेश महामंत्री रतनदीप सिंह ने कहा कि संगठन अपनी मासिक बिजनेस मीट के माध्यम से प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि व्यापारी एक-दूसरे के व्यवसाय को प्राथमिकता दें और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें, तो रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है। उन्होंने बताया कि युवा कैट का विजन 'Connect • Collaborate • Grow' केवल एक नारा नहीं बल्कि व्यापारिक समुदाय को जोड़ने, सहयोग बढ़ाने और सामूहिक विकास की सोच है।

व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर कैट ने की पुलिस उपायुक्त से चर्चा

रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी के नेतृत्व में कैट छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) तारकेश्वर पटेल से सौजन्य भेंट कर उन्हें नवीन दायित्व के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित कीं। इस अवसर पर व्यापारियों की सुरक्षा, सुगम व्यापारिक वातावरण तथा शासन-प्रशासन एवं व्यापारिक समुदाय के बीच बेहतर समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा हुई।

प्रतिनिधिमंडल में कैट छत्तीसगढ़ के चेयरमेन जितेन्द्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन, वाइस चेयरमेन सुरिन्दर सिंह, जीवत बजाज, प्रदेश महामंत्री अवनीत सिंह, कोषाध्यक्ष विजय पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, वासु माखीजा, राम मंधान, भरत जैन, राकेश ओचवानी एवं शंकर बजाज सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अमर पारवानी ने कहा कि कैट सदैव व्यापारियों एवं शासन-प्रशासन के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग का मजबूत सेतु रहा है। सुरक्षित एवं अनुकूल व्यापारिक वातावरण आर्थिक विकास की आधारशिला है। कैट व्यापारियों के हितों की रक्षा, व्यापार संवर्धन तथा उद्योग एवं व्यापार से जुड़े सकारात्मक प्रयासों में प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से व्यापारियों को और अधिक सुरक्षित एवं विश्वासपूर्ण वातावरण प्राप्त होगा। पुलिस उपायुक्त तारकेश्वर पटेल ने कैट प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रायपुर पुलिस व्यापारियों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल ने की पत्रकारों से चाय पर चर्चा

रायपुर। रायपुर प्रेस क्लब के गौरव को वापस लौटाने और इसके कायाकल्प की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। रायपुर प्रेस क्लब भवन के जीर्णोद्धार (Renovation) प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई के क्रम में जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल एवं रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने प्रेस क्लब भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों उच्च अधिकारियों ने भवन के आवश्यक विकास कार्यों को लेकर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की, जिसके बाद पत्रकारों से चाय पर एक अनौपचारिक भेंट एवं आत्मीय संवाद भी हुआ। निरीक्षण के दौरान जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल और नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने प्रेस क्लब परिसर का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने भवन को आधुनिक और पत्रकारों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए जीर्णोद्धार कार्यों पर जोर दिया। इस दौरान जोन कमिश्नर 4 दिव्या चन्द्रवंशी सहित नगर निगम और जनसंपर्क विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने विकास कार्यों के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की।

इस अनौपचारिक संवाद और 'चाय पर चर्चा' कार्यक्रम में रायपुर मीडिया जगत के कई दिग्गज एकजुट हुए। इस खास अवसर पर प्रेस क्लब पदाधिकारी अध्यक्ष मोहन तिवारी, उपाध्यक्ष गौरव शर्मा, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, महासचिव दिलीप साहू, संयुक्त सचिव निवेदिता साहू और दिलीप जांगड़े के साथ 'जनता से रिश्ता' के प्रधान संपादक पप्पू फरिश्ता, राज. संपादक जाकिर घुरसेना, 'नवभारत' के संपादक राजेश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश शर्मा, बृजेश चौबे, प्रशांत शर्मा, प्रदीप दुबे (मामा), संजीव वर्मा, रवि भोई, प्रफुल पारे, मनीष वोरा, जावेद खान, मुकेश वर्मा और यशवंत धोटे उपस्थित रहे। जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक संजीव तिवारी, संतोष मौर्या, और संयुक्त संचालक बालमुकुंद तंबोली समेत जनसंपर्क और नगर निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

90 वर्षीय महिला का जटिल महाधमनी एन्यूरिज्म का सफल उपचार

रायपुर। एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल, रायपुर ने 90 वर्षीय महिला का जटिल एंडोवैस्कुलर एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर (EVAR) सफलतापूर्वक किया है। यह छत्तीसगढ़ में 90 वर्ष या उससे अधिक आयु के मरीज पर इस प्रकार की पहली सफल प्रक्रिया मानी जा रही है। मरीज पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल की ओपीडी में पहुंची थीं। जांच में पता चला कि उनकी महाधमनी (एओर्टा) के निचले हिस्से में 64 मिमी का बड़ा एन्यूरिज्म (धमनी में असामान्य सूजन) था, जिसमें रक्त का थक्का भी मौजूद था। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि एन्यूरिज्म कभी भी फट सकता था, जिससे मरीज की जान को गंभीर खतरा था। मामला इसलिए भी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि मरीज की रक्तवाहिनी अत्यधिक घुमावदार थी और किडनी व आंतों को रक्त पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण धमनियां एन्यूरिज्म के बहुत करीब स्थित थीं।

यदि इस स्थिति में एन्यूरिज्म फट जाता, तो मरीज के बचने की संभावना लगभग शून्य होती। वहीं, 90 वर्ष की आयु और पहले से मौजूद हृदय संबंधी समस्याओं के कारण पारंपरिक ओपन सर्जरी भी अत्यधिक जोखिमपूर्ण थी। ऐसे में विशेषज्ञों ने न्यूनतम चीरा लगाने वाली एंडोवैस्कुलर तकनीक (EVAR) को सबसे सुरक्षित विकल्प माना। चुनौती यह थी कि एन्यूरिज्म को पूरी तरह सुरक्षित किया जाए, लेकिन किडनी और आंतों तक रक्त की आपूर्ति प्रभावित न हो। विशेषज्ञ टीम ने 26 जून 2026 को विशेष "रिवर्स स्लाइडिंग तकनीक" और बड़े स्टेंट ग्राफ्ट का उपयोग करते हुए यह जटिल प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। इस प्रक्रिया का नेतृत्व करने वाले डॉ. सुमंता शेखर पाढ़ी, वरिष्ठ सलाहकार हृदय रोग एवं क्लीनिकल लीड, एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल, रायपुर ने कहा, "मरीज की आयु और रक्तवाहिनी की जटिल संरचना के कारण यह बेहद चुनौतीपूर्ण मामला था।

एटी ज्वेलर्स में आध्यात्मिकता के साथ मनाया जा रहा "जोहार जगन्नाथ"

09 से 16 जुलाई तक आयोजित हुई भव्य धार्मिक महोत्सव

रायपुर। मध्य भारत के प्रतिष्ठित ज्वेलरी ब्रांड अनोपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड (AT पैलेस, कोतवाली चौक, रायपुर) द्वारा गत वर्ष आयोजित ए टी जोहार जगन्नाथ कार्यक्रम को श्रद्धालुओं का अपार स्नेह, विश्वास एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उस पावन अवसर पर हजारों भक्तों ने भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्रीचरणों में अपनी मनोकामनाएँ अर्पित की थीं तथा अनेक श्रद्धालुओं ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन एवं दिव्य अनुभूतियों का अनुभव साझा किया था। इन्हीं भावनाओं, आस्था और भक्तिभाव के उन अविस्मरणीय क्षणों को पुनः जीवंत करने के उद्देश्य से इस वर्ष ए टी जोहार जगन्नाथ 2026 का आयोजन 09 से 16 जुलाई 2026 तक AT पैलेस, कोतवाली चौक, रायपुर में किया जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा की भव्य स्थापना की जाएगी। इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आध्यात्मिक व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत श्रीक्षेत्र पुरी से भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का पावन महाप्रसाद मंगवाया जाएगा तथा स्थापना दिवस से लेकर रथयात्रा तक प्रतिदिन श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया जाएगा। यह महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि भगवान की कृपा, प्रेम और आशीर्वाद का साक्षात प्रतीक माना जाता है। अनोपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स के चेयरमैन तिलोकचंद बरड़िया ने सभी श्रद्धालुओं से भावपूर्ण आग्रह करते हुए कहा है कि वे AT पैलेस पहुँचकर "मनोकामना पेटी" में अपनी इच्छाएँ, प्रार्थनाएँ एवं संकल्प अवश्य लिखें। कार्यक्रम के उपरांत इन सभी मनोकामनाओं को भगवान श्री जगन्नाथ जी की नगरी पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रभु के श्रीचरणों में समर्पित किया जाएगा

उपमुख्यमंत्री ने मनोकामना रथ को दिखाई हरी झंडी

भगवान जगन्नाथ रथयात्रा के अवसर पर "जोहार जगन्नाथ" कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के माननीय उपमुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा भगवान जगन्नाथ के मनोकामना रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि "जोहार जगन्नाथ" केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की भक्ति, आस्था और सेवा का पावन अभियान है। उन्होंने कहा कि मनोकामना रथ के माध्यम से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएँ प्रभु के श्रीचरणों तक पहुँचेंगी।

मैट्स विश्वविद्यालय में दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस संपन्न

रायपुर। वैश्विक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दौर में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के बदलते स्वरूप पर चर्चा करने के लिए, मैट्स यूनिवर्सिटी के मैट्स स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस द्वारा दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन किया गया. इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय ट्रांसफार्मिंग लाइब्रेरिज थ्रु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) फॉर विकसित भारत/2047 (एनसीटीएलएआई-व्हीबी/2047)" था। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन किया गया।

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष और कन्वेनर डॉ. कल्पना चंद्राकर द्वारा विभाग की उपलब्धियों और कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य के विस्तृत विवरण के साथ विचार साझा किए, उन्होंने बताया कि कैसे एआई तकनीक आने वाले समय में पुस्तकालयों की स्थिति को प्रभावित करेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डा. अमित केशव, प्रोफेसर केमिकल इंजीनियरिंग, एनआईटी रायपुर, विशिष्ट अतिथि श्री डा. सुनील कुमार सतपथी, डिप्टी लाइब्रेरियन, एनआईटी रायपुर और माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) के. पी. यादव ने 'एआई और विकसित भारत' के संकल्प पर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। कुलपति महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को साल 2047 तक विकसित बनाने में तकनीक और डिजिटल साक्षरता का सबसे बड़ा योगदान होगा, जिसमें पुस्तकालयों को मॉडर्न एआई टूल्स से लैस करना एक क्रांतिकारी कदम है. मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने भी लाइब्रेरी ऑटोमेशन, डेटा सुरक्षा और मशीन लर्निंग के महत्व पर जोर दिया. कॉन्फ्रेंस के दौरान रिसर्च स्कॉलर्स, शिक्षाविदों और छात्रों द्वारा एआई-एन्हांस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज, ओपन-एक्सेस, डिजीटल ना ॅलेज मैनेजमेंट, एथीकल इश्यूज और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 जैसे विषयों पर विभिन्न राज्यों से आए शोधकर्ताओं के 40 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए।

PSU NLC India और NALCO मिलकर लगाएंगे 1,080 MW का पावर प्लांट

नई दिल्ली। भारत की दो बड़ी नवरत्न सरकारी कंपनियों NLC India और NALCO ने एक बड़े पावर प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिला लिया है. NLC India ने एक फाइलिंग में बताया कि दोनों कंपनियों ने ओडिशा के अंगुल में 1,080 मेगावाट क्षमता वाले कोयला आधारित कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट के विकास के लिए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट (JVA) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस परियोजना को NLC India और NALCO संयुक्त रूप से विकसित करेंगी और इसमें दोनों की हिस्सेदारी 50:50 रहेगी.यह समझौता 8 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी की मौजूदगी में हुआ. इस परियोजना को दोनों कंपनियों के बीच रणनीतिक सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.इस खबर के बाद गुरुवार को NLC India और NALCO के शेयर फोकस में रहेंगे. NLC India का शेयर 2.7% नीचे 294 रुपये पर बंद हुआ है. वहीं, NALCO का शेयर 2.47% ऊपर 351 रुपये पर बंद हुआ है.

1,080 MW क्षमता का होगा पावर प्रोजेक्ट

जॉइंट वेंचर के तहत ओडिशा के अंगुल में 4 यूनिट्स वाला थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा. हर यूनिट की क्षमता 270 मेगावाट होगी, जिससे कुल उत्पादन क्षमता 1,080 मेगावाट हो जाएगी.यह प्लांट मुख्य रूप से NALCO की विस्तार योजनाओं के लिए लॉन्ग टर्म और भरोसेमंद बिजली सप्लाई सुनिश्चित करेगा. बढ़ती औद्योगिक मांग को देखते हुए यह परियोजना कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है.

50:50 हिस्सेदारी के साथ बनेगी नई कंपनी

इस परियोजना के लिए एक अलग जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी, जिसमें NLC India और NALCO की बराबर यानी 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी.नई कंपनी परियोजना के विकास, वित्तपोषण, निर्माण, स्वामित्व और संचालन की पूरी जिम्मेदारी संभालेगी. इससे परियोजना को एक समर्पित प्रबंधन ढांचा मिलेगा और कामकाज में बेहतर दक्षता आने की उम्मीद है.

सरकार की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति को मिलेगा बल

सरकार लगातार ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास को मजबूत करने पर जोर दे रही है. NLC India और NALCO के बीच यह साझेदारी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है.यह परियोजना देश में संसाधनों के बेहतर उपयोग, ऊर्जा उपलब्धता बढ़ाने और औद्योगिक विस्तार को समर्थन देने में मदद कर सकती है।

TEC और BECIL के बीच MoU साइन

5G ब्रॉडकास्ट और डायरेक्ट-टू-मोबाइल (D2M) तकनीक पर मिलकर करेंगे रिसर्च

नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश के टेलीकॉम (दूरसंचार) और ब्रॉडकास्टिंग (प्रसारण) क्षेत्र को हाई-टेक बनाने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग (DoT) की तकनीकी शाखा 'दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र' (TEC) ने 'ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड' (BECIL) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) किया है। इस रणनीतिक साझेदारी का मुख्य मकसद दोनों विभागों की विशेषज्ञता को मिलाकर देश में नई और आधुनिक ब्रॉडकास्टिंग तकनीकों को तेजी से बढ़ावा देना है। नई दिल्ली में आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम में इस समझौते पर TEC के उप महानिदेशक देवेंद्र सिंह और BECIL के उप महाप्रबंधक रमित लाला ने हस्ताक्षर किए।

क्या है D2M और 5G ब्रॉडकास्टिंग?

इस समझौते के तहत दोनों प्रमुख संस्थान मिलकर कई एडवांस तकनीकों पर रिसर्च और स्टडी करेंगे। इनमें सबसे खास और क्रांतिकारी तकनीक है 'डायरेक्ट-टू-मोबाइल' (D2M) और 5G ब्रॉडकास्टिंग।

बिना इंटरनेट लाइव टीवी: इस तकनीक के कमर्शियल रोलआउट के बाद देश के नागरिक बिना इंटरनेट डेटा पैक या बिना सिम कार्ड के भी अपने मोबाइल फोन पर सीधे लाइव टीवी, वीडियो और समाचार देख सकेंगे।

रेडियो जैसी तकनीक: यह तकनीक बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे मोबाइल में बिना इंटरनेट या सिम के एफएम रेडियो (FM Radio) चलता है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भी बिना बफरिंग के वीडियो कंटेंट पहुँचाया जा सकेगा।

BEML ने बिजनेस इनोवेशन अवार्ड्स 2026 में छह पुरस्कार जीते

नई दिल्ली। सरकारी स्वामित्व वाली बीईएमएल लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि उसने बिजनेस इनोवेशन अवार्ड्स 2026 के चौथे संस्करण में छह पुरस्कार जीते हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बीईएमएल को उसके प्रदर्शन, नवाचार, संगठनात्मक उत्कृष्टता, बुनियादी ढांचा विकास, कार्यस्थल संस्कृति और कॉर्पोरेट संचार के लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वहीं, बीईएमएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शांतनु रॉय को वर्ष के दूरदर्शी सार्वजनिक क्षेत्र के नेता के रूप में सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार बीईएमएल की वरिष्ठ नेतृत्व टीम ने ग्रहण किए। निदेशक (वित्त) अनिल जेरथ ने सीएमडी शांतनु रॉय की ओर से वर्ष के दूरदर्शी सार्वजनिक क्षेत्र के नेता का पुरस्कार स्वीकार किया और साथ ही वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का पुरस्कार भी प्राप्त किया।

मानव संसाधन निदेशक देबी प्रसाद सतपथी को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र कार्यस्थल संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि खनन एवं निर्माण निदेशक संजय सोम को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना पीएसयू पुरस्कार मिला।रेल एवं मेट्रो के कार्यकारी निदेशक ओम प्रकाश सिंह को सार्वजनिक क्षेत्र नवाचार उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ, और कॉर्पोरेट संचार प्रमुख तापश तालुकदार ने सार्वजनिक क्षेत्र विपणन एवं संचार पुरस्कार स्वीकार किया। यह सम्मान BEML के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में, कंपनी ने अपना अब तक का उच्चतम वार्षिक कारोबार, अनुसंधान और विकास में उच्चतम निवेश, सबसे बड़ा ऑर्डर बुक और उच्चतम पूंजीगत व्यय दर्ज किया।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान, बीईएमएल ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट भी वितरित की और देश की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बीआरएस21 रोप शॉवेल विकसित की, जो नवाचार, स्वदेशी विनिर्माण और सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल पर इसके ध्यान को मजबूत करती है। कंपनी ने कहा कि वह अपने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, अपनी प्रतिभा के आधार को बढ़ाने और भारत की अग्रणी विविध इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनियों में से एक के रूप में अपनी स्थिति का विस्तार करने पर केंद्रित है।

SECL ने जीता ग्रीन ट्रांजिशन लीडरशिप अवार्ड

नई दिल्ली। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) को टाइम्स इंटरनेट इकोप्रेनर्स अवार्ड्स 2026 में 'ग्रीन ट्रांजिशन लीडरशिप अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। सतत खनन और पर्यावरण संरक्षण में अपनी पहलों के लिए कोल इंडिया की इस सहायक कंपनी को यह विशेष मान्यता प्राप्त हुई है, साथ ही कंपनी चालू वित्त वर्ष में 50 मिलियन टन (एमटी) कोयला उत्पादन को पार करने वाली कोल इंडिया की पहली सहायक कंपनी बन गई है। यह पुरस्कार एसईसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हरीश दुहान ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ग्रहण किया।

कंपनी के अनुसार, यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक तरीके से खदानों को बंद करने, भूमि सुधार और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ खनन प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाने में एसईसीएल के प्रयासों को मान्यता देता है। एक महत्वपूर्ण परिचालन उपलब्धि हासिल करते हुए, एसईसीएल ने वित्त वर्ष 2026-27 में 50 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है, और चालू वित्त वर्ष में यह उपलब्धि हासिल करने वाली कोल इंडिया की पहली सहायक कंपनी बन गई है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कोयला उत्पादन में 9.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। यह उपलब्धि एसईसीएल की प्रमुख खनन परियोजनाओं के दमदार प्रदर्शन के कारण हासिल हुई। दिपका परियोजना ने 11.8 मीट्रिक टन, गेवरा परियोजना ने 11.7 मीट्रिक टन और कुसमुंडा परियोजना ने 9.7 मीट्रिक टन का उत्पादन किया। सीआईसी कोलफील्ड्स ने 8.8 मीट्रिक टन, रायगढ़ क्षेत्र ने 5.9 मीट्रिक टन और कोरबा क्षेत्र ने 2.1 मीट्रिक टन का योगदान दिया, जिससे कंपनी के उत्पादन में वृद्धि को बल मिला। इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए दुहान ने कहा कि यह पुरस्कार सतत विकास और जिम्मेदार खनन के प्रति एसईसीएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा हमारी विकास रणनीति के समान रूप से महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। हम जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल खनन प्रथाओं को बढ़ावा देना जारी रखते हुए, सुरक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी-आधारित खनन कार्यों के माध्यम से देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।"

अदाणी दिवस पर पीईकेबी एवं पीसीबी खदान क्षेत्रों में रक्तदान एवं वृक्षारोपण अभियान का आयोजन

अंबिकापुर। अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी के जन्मदिवस के अवसर पर 'अदाणी दिवस' के तहत पीईकेबी एवं पीसीबी खदान क्षेत्रों में रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खनन परियोजना के कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय एवं सहयोगी संस्थाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।रक्तदान शिविर में खनन परियोजना के कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 472 यूनिट रक्तदान किया। यह रक्त क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोगी रहेगा।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए पीईकेबी परियोजना क्षेत्र में 11.293 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 28,231 पौधों का रोपण किया गया। कुल 300 लोगों ने पौधारोपण में भाग लिया। स्थानीय जलवायु के अनुरूप पौधों का चयन कर हरित आवरण बढ़ाने की दिशा में कार्य किया गया।इस अवसर पर परियोजना प्रतिनिधि ने कहा, "अदाणी दिवस पर आयोजित रक्तदान एवं वृक्षारोपण अभियान समाज और पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। रक्तदान के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता और वृक्षारोपण के जरिए हरित भविष्य की दिशा में यह हमारा सामूहिक प्रयास है।" कार्यक्रम के सफल आयोजन में अदाणी समूह के कर्मचारियों, प्रबंधन, स्थानीय समुदाय, उद्यानिकी टीम, खनन विभाग एवं प्रशासनिक इकाइयों का योगदान रहा। साथ ही जैन पाइप ट्रेडर्स, गंगा सागर चौबे, एमएम सेल्स तथा खनन संविदाकारों ने भी सहयोग प्रदान किया।

श्रीमती शालू जिन्दल को 'सीएसआर विजनरी लीडर ऑफ द ईयर' का सम्मान

नई दिल्ली। जिन्दल फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती शालू जिन्दल (Shalu Jindal) को सामाजिक विकास के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और अनुकरणीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 'सीएसआर विजनरी लीडर ऑफ द ईयर' अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नई दिल्ली के एयरोसिटी स्थित होटल प्राइड प्लाजा में 'द ब्रेनालिटिक्स' द्वारा हाल ही में आयोजित '7वें भारत सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2026' में प्रदान किया गया। यह सम्मान देश भर में विभिन्न समुदायों का जीवन स्तर सुधारने और उनके कल्याण के लिए जिन्दल फाउंडेशन के माध्यम से श्रीमती शालू जिन्दल द्वारा किये गए दूरदर्शी और समर्पित प्रयासों की कड़ी में मील का एक पत्थर है। उनके कुशल मार्गदर्शन में फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, आजीविका, जल और स्वच्छता, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, पर्यावरणीय विकास, कला व संस्कृति और सामाजिक उत्थान जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराई है।

इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्रीमती शालू जिन्दल ने इस अवार्ड को फाउंडेशन की सेवा यात्रा से जुड़े सहयोगियों, साझेदारों और टीम के सामूहिक प्रयासों और उनके समर्पण का सम्मान बताया, जो सामाजिक उत्थान के पवित्र प्रयासों में निरंतर योगदान कर रहे हैं। जिन्दल फाउंडेशन के बारे में – जिन्दल स्टील की सामाजिक सेवा शाखा 'जिन्दल फाउंडेशन' देशभर में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और समाज में समान अवसरों व खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यावरण संरक्षण, खेल तथा कला एवं संस्कृति जैसे विविध क्षेत्रों में जनकल्याणकारी पहल के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।

SECL ने कियाब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट में कोल इंडिया का प्रतिनिधित्व

नई दिल्ली। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता-2026 के तहत हैदराबाद में 14 से 16 जुलाई तक आयोजित हो रही ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट में साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने कोल इंडिया लिमिटेड का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर एसईसीएल के निदेशक (मानव संसाधन) श्री बिरंची दास ने "ब्रिक्स+ देशों में सर्वोत्तम प्रथाएं" विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में भाग लेते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के समक्ष कोल इंडिया की मानव संसाधन, कर्मचारी कल्याण एवं सामाजिक विकास संबंधी प्रमुख पहलों को साझा किया।

अपने संबोधन में उन्होंने देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में शामिल कोल इंडिया के 2.2 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए संचालित कर्मचारी कल्याण, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास तथा सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार जन-केंद्रित नीतियों और सहभागी कार्यसंस्कृति के माध्यम से संगठन उत्पादकता और कर्मचारी हितों के बीच संतुलन स्थापित कर रहा है। उन्होंने एसईसीएल की सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) आधारित पहलों का भी उल्लेख किया। "एसईसीएल के सुश्रुत" एवं "एसईसीएल की धड़कन" जैसी योजनाओं के माध्यम से कोयलांचल क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलावों की जानकारी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ साझा की। उल्लेखनीय है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता-2026 की थीम "रेज़िलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी" है। इसी क्रम में आयोजित तीन दिवसीय इस अंतरराष्ट्रीय समिट में 50 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों के साथ भारतीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, श्रम विशेषज्ञ एवं शिक्षाविद शामिल हुए।

कलिंगा विवि में मनाया गया योग दिवस

रायपुर। कलिंगा विश्वविद्यालय में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान संकाय (योग विभाग) एवं डीन छात्र कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम "स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग" (Yoga for Healthy Aging) रही।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. संदीप गांधी एवं विज्ञान संकाय के डीन डॉ. अंजनयुलु बेंदी के उद्बोधनों से हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ ॐ के सामूहिक उच्चारण के साथ किया गया। इसके पश्चात योग विभाग के सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. राजेश मानिक द्वारा विभिन्न योगासनों का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने प्रत्येक योगासन के लाभों की विस्तृत जानकारी भी प्रतिभागियों को प्रदान की। योग विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. धनंजय जैन के निर्देशन में प्रतिभागियों ने ध्यान (मेडिटेशन) का अभ्यास किया। योग हॉल में निर्धारित योग प्रोटोकॉल के अनुसार 30 मिनट का योग सत्र आयोजित किया गया।

इस सत्र का उद्देश्य प्रतिभागियों को योग के समग्र लाभों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के अंत में डॉ. धनंजय जैन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। योग सत्र के उपरांत प्रतिभागियों को पौष्टिक प्रसाद के रूप में अंकुरित अनाज (स्प्राउट्स) एवं नींबू पानी वितरित किया गया, जिससे सभी प्रतिभागियों ने स्वयं को तरोताज़ा महसूस किया। कलिंगा विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह पूर्णतः सफल रहा। इस आयोजन ने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व को प्रभावी रूप से रेखांकित किया।

जून 2026 की टॉप 10 कार

टाटा पंच | 21,006

टाटा नेक्सॉन | 18,335

सुजुकी डिजायर | 17,899

सुजुकी वैगनआर | 16,952

सुजुकी अर्टिगा | 16,111

सुजुकी स्विफ्ट | 15,215

महिंद्रा स्कॉर्पियो | 14,097

सुजुकी फ्रांक्स | 13,135

सुजुकी बलेनो | 12,488

हुंडई वेन्यू | 10,776

भारत में लॉन्च हुई टाटा सिएरा ईवी

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स द्वारा भारतीय बाजार में कई तरह की कारें ऑफर की जाती हैं. वहीं टाटा द्वारा ईवी सेगमेंट में भी कई कारें ऑफर की जाती हैं. कंपनी द्वारा अब बाजार में नई सिएरा ईवी (Tata Sierra EV) को लॉन्च किया जा चुका है. ऐसे में अगर आप एक नई ईवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप नई टाटा सिएरा ईवी को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं. आज हम आपको टाटा सिएरा ईवी की सभी डिटेल्स के बारे में बताने वाले हैं.

सबसे पहले बात कर लेते हैं नई टाटा सिएरा ईवी की कीमत के बारे में तो नई टाटा सिएरा ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.79 लाख रुपये है. वहीं नई सिएरा ईवी के टॉप वेरिएंट की कीमत 24.79 लाख रुपये है. नई टाटा सिएरा ईवी 4 वेरिएंट में पेश की गई हैं. इसमें Pure, Pure S, Adventure, Empowered और Empowered A शामिल है. नई टाटा सिएरा ईवी के डिजाइन की बात करें तो यह लगभग पेट्रोल-डीजल मॉडल जैसा ही है.

हालांकि, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं. इसमें बॉडी कलर क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, नया बंपर और EV-विशेष डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं. वहीं इस नई SUV में नए 18-इंच एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं, जो इसकी इलेक्ट्रिक पहचान को और मजबूत बनाते हैं. साथ ही नई सिएरा ईवी कई आकर्षक कलर्स में उपलब्ध है।

गिग वर्कर्स और सेल्फ-एम्प्लॉयड के लिए खुशखबरी EPFO जल्द ला सकता है नई यूनिवर्सल PF स्कीम

नई दिल्ली। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी कंपनी में स्थायी नौकरी नहीं करते, बल्कि वह फ्रीलांसिंग कर रहे हैं. साथ ही कई लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए या अपना खुद का काम करके कमाई कर रहे हैं. अब ऐसे लोगों को भी PF के जरिए भविष्य में आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिल सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO अब एक ऐसी यूनिवर्सल प्रोविडेंट फंड (PF) स्कीम पर काम कर रहा है, जिसके जरिए स्वरोजगार करने वाले, गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी भी अपनी रिटायरमेंट के लिए फंड बना सकेंगे. हालांकि, सरकार की ओर से अभी इस योजना का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. आइए जानते हैं डिटेल्स.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, EPFO की नई प्रस्तावित योजना का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिल सकता है जो अभी EPFO के दायरे से बाहर हैं. इसमें-

- **स्वरोजगार (Self-employed) करने वाले लोग**
- **गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स**
- **फ्रीलांसर और कंसल्टेंट**
- **असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी**
- **EPFO से बाहर रहने वाले कुछ अन्य कर्मचारी**

ऐसे में अगर यह नई योजना लागू होती है, तो यह लोग अपनी इच्छा के अनुसार PF खाते में नियमित बचत कर सकेंगे. नई योजना के तहत, सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार रोजाना, साप्ताहिक, मासिक या सालाना योगदान कर सकेंगे. साथ ही जमा राशि पर हर साल ब्याज भी मिलता रहेगा. यह एकदम ऐसे ही होगा जैसे मौजूदा EPF खातों में ब्याज मिलता है. इससे उन लोगों को भी लंबी अवधि की बचत का मौका मिलेगा, जिनकी आय हर महीने एक जैसी नहीं होती है.

टैक्स में भी मिल सकती है राहत

प्रस्तावित योजना में टैक्स लाभ देने पर भी विचार किया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2.5 लाख रुपये तक के वार्षिक योगदान और उस पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स छूट के दायरे में रखा जा सकता है. हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है.नई योजना का एक खास पहलू यह भी हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद पूरी रकम एक साथ निकालना जरूरी नहीं होगा. सदस्य चाहें तो अपना पैसा EPFO में ही रहने दे सकते हैं और जरूरत के अनुसार किस्तों में रकम निकाल सकते हैं. यह व्यवस्था म्यूचुअल फंड के सिस्टेमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) की तरह हो सकती है. बताया जा रहा है कि भविष्य में यह सुविधा मौजूदा EPF खाताधारकों को भी दी जा सकती है.

EPFO इस योजना के लिए जरूरी आईटी सिस्टम और डिजिटल ढांचे की तैयारी शुरू कर चुका है. हालांकि उसे अभी सरकार की ओर से औपचारिक अनुमति नहीं मिली है. सरकार का उद्देश्य सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है, जिससे केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि असंगठित क्षेत्र और गिग इकोनॉमी से जुड़े लोग भी रिटायरमेंट के लिए बचत कर सकें।